NITI Aayog

सत्यमेव जयते
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Government of India

Food and Agriculture Organization of the United Nations

राष्ट्रीय संवाद

2030 की ओर अग्रसर भारतीय कृषि

किसानों की आय बढ़ाने, पोषण सुरक्षा एवं सतत खाद्य प्रणाली के लिए दिशा एवं उपाय

भारतीय कृषि में संरचनात्मक सुधार तथा शासन संबंधित मुद्दे

डॉ. सीमा बाथला तथा डॉ. सिराज हुसैन

यह चर्चा लेख स्वतंत्रता के बाद से भारतीय कृषि द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख संरचनात्मक मुद्दों से संबंधित है। संघीय आर्थिक संबंधों तथा कृषि विकास के प्रति साझा जिम्मेदारियों के संदर्भ में, यह लेख कृषि में अन्य आर्थिक क्षेत्रों की तुलना में पूँजी निर्माण और सब्सिडी पर खर्च की जांच करता है। यह सब्सिडी व्यवस्था में सुधार (इनपुट और आउटपुट दोनों से संबंधित) और 2020 में अधिनियमित कृषि विपणन कानूनों के निहितार्थ पर विचार रखता है। कृषि क्षेत्र (सिंचाई सहित) को हमेशा सार्वजनिक व्यय में अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता मिली है। ज्यादातर खर्च निवेश के बजाय इनपुट सब्सिडी के प्रति अधिक रहा है, जो नियत समय में कृषि विकास को प्रभावित कर सकता है। लेख में प्रस्तावित संस्थागत, मूल्य एवं विधायी सुधार और संरचनात्मक परिवर्तन बताते हैं कि कृषि क्षेत्र को हैंडहोल्डिंग (सहायता) की आवश्यकता है। भारत सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर ग्रामीण बुनियादी ढाँचे तथा मूलभूत सुविधाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर) में तेजी लाने के लिए काम करना चाहिए। विशिष्ट क्षेत्रों के साथ-साथ छोटे और सीमांत किसानों को सहायता के लिए लक्षित करना चाहिए और एक प्रतिस्पर्धी माहौल बनाना चाहिए जो निवेश, उत्पादकता और विपणन दक्षता को प्रेरित करता होs। किसानों और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए उपज के उत्पादन और विपणन से संबंधित कार्ययोजना तैयार करने में राज्यों को और अधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। समन्वय तथा नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा संस्थानों की एक बड़ी भूमिका की आवश्यकता है।

पेपर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

मुख्य शब्द: संरचनात्मक सुधार, शासन, सब्सिडी, कृषि विपणन कानून, निवेश